संख्या-6 /2018/340/60-2-18-2/3(6)/12

प्रेषक,

मासूम अली सरवर
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 20 फरवरी, 2018

विषय : अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुपूरक पुष्टाहार राज्य योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-800/बा0वि0परि0/लेखा/2017-18, दिनांक 14.12.2017, संख्या-868/बा0वि0परि0/लेखा/2017-18, दिनांक 09.01.2018 एवं संख्या-967/बा0वि0 परि0/लेखा/2017-18, दिनांक 13.02.2018 संदर्भ में अवगत कराना है कि अनुदान संख्या-49 के अधीन पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार के लिए मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 224027.78 लाख (रूपये बाइस अरब चालीस करोड़ सत्ताइस लाख अठहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष गत वर्ष की देयता के भुगतान तथा चालू वित्तीय वर्ष के सम्भावित व्यय के दृष्टिगत प्रथम त्रैमास हेतु रूपये 46088.90492 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-24/2017/1559/60-2-17-2/3(6)/12, दिनांक 14.06.2017 एवं रूपये 22900.00 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-46/2017/2463/60-2-17-2/3(6)/12, दिनांक 17.10.2017 द्वारा निर्गत की गयी है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-49 के अधीन पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार के लिए मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 224027.78 लाख (रूपये बाइस अरब चालीस करोड़ सत्ताइस लाख अठहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष अनुपूरक पुष्टाहार हेतु सम्भावित व्यय के दृष्टिगत आवश्यक धनराशि रूपये 45500.00 लाख (रूपये चार अरब पचपन करोड़ मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण संगत मदों में प्रतिमाह की वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि को किसी भी दशा में पी0एल0ए0 खाते/बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(2) स्वीकृति धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/निर्देशों के अनुसार व्यय किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।

(4) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बन्ध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत किये जाये ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई न हो।

(5) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0125-पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (के.50/रा.50-के.+रा.) के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के नामे डाला जायेगा।

4. ये आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मासूम अली सरवर)
विशेष सचिव

संख्या-6/2018/340(1)/60-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1।
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in